RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 04 AUGUST TO 10 AUGUST 2021 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 06 ■ अंक 49 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

शेयर बाजार को नया मुकाम, पहली बार सेंसेक्स 54 हजार अंक के पार, निफ्टी की लंबी छलांग Page 2

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन चीजों की बढ़ाई डेडलाइन Page 3

ई-रुपी से लाभार्थी को 100 प्रतिशत लाभ सुनिश्चित हो सकेगा : उद्योग Page 5

editoria!

अर्थव्यवस्था में बढ़त

महामारी की दूसरी लहर थमने के साथ औद्योगिक गतिविधियों में तेजी के रूझान हैं. जून में आठ प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों- कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, शोधित उत्पाद, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और बिजली- में 8.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. पिछले साल जून में इन क्षेत्रों में 12.4 प्रतिशत का संकुचन हुआ था. चालू वित्त वर्ष के पहले तीन महीनों में प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि आगे के लिए अच्छा संकेत है. इनके अलावा, घरेलू उड़ान, बाजारों में आवाजाही, यातायात आदि अहम कारोबारों में ठोस बढ़त दर्ज की गयी है. मई की तुलना में जून में उड़ानों में 47 फीसदी की बड़ी बढ़ोतरी हुई है. शहरी इलाकों में लोग बाजारों में जा रहे हैं और राजमार्गों पर यातायात भी बढ़ता जा रहा है. गूगल मोबिलिटी इंडेक्स के अनुसार, 26 जुलाई को खुदरा बाजारों- रेस्तरां, दुकान आदि, में जानेवालों की संख्या कोरोना महामारी से पहले के स्तर से 20 फीसदी ही कम है. दूसरी लहर के सबसे भयावह दिनों से ठीक पहले 23 अप्रैल को यह आंकड़ा 46 फीसदी कम रहा था. अब कई शहरों में सिनेमाघरों और अन्य प्रतिष्ठानों के खुलने से इसमें और सुधार आने की उम्मीद है. अनेक राज्यों में अब शिक्षण संस्थाओं को खोलने की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है. वाहनों समेत विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद-बिक्री में भी इजाफा हो रहा है. इन सूचकों से स्पष्ट है कि महामारी के कारण मंदी की चपेट में आयी अर्थव्यवस्था में सुधार अपेक्षित गति से हो रहा है तथा सरकार के राहत पैकेज का सकारात्मक लाभ भी व्यवसायों को मिल रहा है. लेकिन पूंजी निर्माण में यानी बचत अभी भी गति धीमी है तथा अनेक कारोबारी गतिविधियां धीरे-धीरे अग्रसर हो रही हैं. निश्चित रूप से इसका एक असर आमदनी पर पड़ा है. जानकारों का मानना है कि महामारी, लॉकडाउन, मुद्रास्फीति आदि से परिवारों की आय कम हुई, पर खर्च बढ़ गया. स्थिति पटरी पर आ तो रही है और लोगों में भविष्य के लिए आशा व अपेक्षा भी है, किंतु उपभोग एवं व्यय को लेकर लोग सतर्कता बरत रहे हैं. इस कारण उपभोग का स्तर नीचे है और मांग में अपेक्षित उछाल नहीं है. लेकिन संकट की किसी भी स्थिति में ऐसा होना स्वाभाविक है. इसके अलावा एक बड़ा कारक कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका भी है. आधिकारिक आकलनों की मानें, तो 40 करोड़ लोग संक्रमण के खतरे के दायरे में हैं. इस माह से टीकाकरण अभियान में तेजी आने की उम्मीद है. जैसे-जैसे लोगों को टीके की खुराक मिलती जायेगी, वैसे वैसे संक्रमण का जोखिम कम होता जायेगा. इसके बावजूद हर किसी को सतर्क रहते हुए कामकाज करना है क्योंकि अभी भी हर दिन संक्रमित होनेवाले लोगों की संख्या 40 हजार से ऊपर है और मौतें भी हो रही हैं. सावधानी से ही हम तीसरी लहर को टाल सकते हैं तथा अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को इस वित्त वर्ष में दो अंकों तक ले जा सकते हैं.

कच्चा तेल हुआ और भी सस्ता

18 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमते स्थिर

नयी दिल्ली। एजेंसी

दुनिया की दो बड़ी ताकतों अमेरिका और चीन में कोरोना की नई लहर ने तेल उत्पादक देशों के माथे पर बल ला दिए हैं। इसी के चलते वैश्विक तेल बाजार में मंदी का माहौल दिखाई दे रहा है। डब्ल्यूटीआई क्रूड में 2.81 प्रतिशत और ब्रेंट क्रूड में 2.21 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 18वें दिन कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। भारत में 17 जुलाई के बाद से पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में बुधवार को भी इंडियन ऑयल (घ्ध्ण) के पंप पर पेट्रोल 101.84 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.87 रुपये प्रति लीटर के दाम पर मिल रहा है। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में भी आज प्रति लीटर पेट्रोल का भाव 107.83 रुपये और डीज़ल का भाव 97.45 रुपये प्रति लीटर पर है। मई में विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद से यह पहला मौका है जब लगातार इतने लंबे वक्त तक तेल की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है। बता दें कि मई में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से चार मई से 42 बार कीमतों में बदलाव हुआ है। इस बीच पेट्रोल 11.52 रुपये प्रति लीटर और डीजल 9.08 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है।

ग्लोबल मार्केट में मंदी

अमेरिका और चीन में कोरोना की ताजा लहर के चलते ग्लोबल आयल मार्केट में मंदी का माहौल है। इसके चलते मंगलवार को डब्ल्यूटीआई क्रूड (ऊ्ध ण्ल्) 2.81 फीसदी कम हो कर 69.35 डॉलर प्रति बैरल तक गिर गया। इसी तरह ब्रेंट क्रूड

2.21 फीसदी कम हो कर 71.25 डॉलर पर आ गया था। हालांकि, बाद में इसमें कुछ सुधार हुआ और बाजार बंद होते समय ब्रेंट क्रूड 72.56 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ था। वहां यूएस वेस्ट टैक्सास इंटरमीडियएट या डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 70.56 डॉलर पर प्रति बैरल पर बंद हुआ था।

लखनऊ में भोपाल के मुकाबले पेट्रोल 11.28 रुपये सस्ता

देश में विभिन्न राज्यों द्वारा लगाए जा रहे भारी भरकम टैक्स की वजह से राज्यों के बीच तेल की कीमतों में काफी अंतर देखा जा रहा है। दो पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात करें तो दोनों राज्यों की राजधानियों में तेल की कीमतों में भारी अंतर है। लखनऊ में इस समय भोपाल के मुकाबले 11.28 रुपये सस्ता पेट्रोल मिल रहा है। भोपाल में जहां पेट्रोल 110.20 रुपये में मिल रहा है। वहीं लखनऊ में इसकी कीमत 98.92 रुपये है। इसी प्रकार लखनऊ में जहां डीजल 90.26 रुपये का है वहीं भोपाल में इसकी कीमत 98.67 रुपये तय की गई है।

इन राज्यों में 100 के पार पेट्रोल

विधानसभा चुनावों के बाद जब से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तब से 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल का भाव 100 रुपये प्रति लीटर के पार जा चुका है। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लद्दाख, कर्नाटक, जम्मू एवं कश्मीर, ओड़िशा, तमिलनाडु, बिहार, केरल, पंजाब, सिक्किम, पुड्डुचेरी, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का नाम शामिल है। 42 दिनों में ही पेट्रोल 11.52 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। वहीं डीजल की कीमत भी पिछले दो महीनों में 9.14 रुपये प्रति लीटर बढ़कर राजधानी में 89.87 रुपये प्रति लीटर हो गई।

इन्फोसिस ने हासिल की दुर्लभ उपलब्धि मार्केट कैप 7 लाख करोड़ रुपये के पार

इससे पहले केवल 3 कंपनियों को मिला है यह मुकाम

नई दिल्ली। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस का मार्केट कैप 7 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। इन्फोसिस यह उपलब्धि हासिल करने वाली देश की चौथी कंपनी है। कंपनी का शेयर मंगलवार को कारोबार के दौरान 1.65 फीसदी की तेजी के साथ 1658.70 रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। बाद में यह 1.39 फीसदी की तेजी के साथ 1654.10 रुपये पर बंद हुआ। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप 704,495.38 करोड़ रुपये पहुंच गया।

रिलायंस इंडस्ट्रीज , टाटा कंसल्टैंसी सर्विसेज और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पहले ही यह मुकाम हासिल कर चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1345027.89 करोड़ रुपये के मार्केट कैप के साथ देश की सबसे मूल्यवान कंपनी है। टीसीएस का मार्केट कैप 1214823.96 करोड़ रुपये और एचडीएफसी बैंक का 793554.87 करोड़ रुपये है।

तिमाही नतीजे

इन्फोसिस का शेयर पिछले एक साल में 72 फीसदी चढ़ा है और इस साल यह अब तक 31.71 फीसदी उछल चुका है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजों की घोषणा के बाद से इस शेयर में 5.18 फीसदी यानी 81 रुपये की तेजी आ चुकी है। जून तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 23 फीसदी बढ़ा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2022 के लिए रेवेन्यू अनुमान बढ़ाकर 14-16 फीसदी कर दिया है।

दुनिया को कच्चा तेल बेचने वाले इस देश में अब पानी की वजह से छिड़ी जंग, जानिए कितने डरावने हैं यहां के हालात

नयी दिल्ली। एजेंसी

ईरान इस समय कई तरह की ऐसी चुनौतियों से जूझ रहा है जो पर्यावरण से जुड़ी हैं। इनमें बढ़ती गर्मी, प्रदूषण, बाढ़ और झीलों का सूख जाना शामिल है। ईरान का खुजेस्तान प्रांत जहां पर तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, वहां पर पानी की कमी से हाल बेहाल हैं। ईरान दुनिया का वो देश है जो अमेरिका से लेकर भारत तक को तेल की सप्लाई करता है। यहां तेल के कुंए तो भरे हुए हैं मगर पानी के कुंए सूखते जा रहे हैं। जो लोग कहते थे कि दुनिया में तीसरा युद्ध पानी के लिए होगा, ईरान में अब यह बात सच होने लगी है। यहां पर पानी का संकट इतना बढ़ गया है कि लोग विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं और पानी के लिए गोलियां खाने को मजबूर हैं।

अप्रैल में वैज्ञानिकों ने किया था आगाह

ईरान में विशेषज्ञों ने पिछले कई सालों से दिन पर दिन खराब होती स्थिति की तरफ ध्यान दिलाया था। इस वर्ष अप्रैल में ईरान के मौसम वैज्ञानिकों ने कहा था कि देश में असाधारण स्तर का सूखा पड़ने और बारिश में भयंकर कमी होने वाली है। ईरान का खुजेस्तान प्रांत जहां पर तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, वहां पर पानी की कमी से हाल बेहाल हैं। यहां पर पानी की कमी के कारण लोग सड़कों पर उतर आए हैं।

सूखती जा रही हैं नदियां

खुजेस्तान प्रांत में काफी लंबे समय से सूखा पड़ा हुआ है। हालात इतने बिगड़ गए कि यहां कि नागरिक विरोध प्रदर्शन के लिए उतर आए और नारे लगाने लगे 'हम प्यासे हैं।' अमेरिका की

स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की मानें तो खुजेस्तान में कभी पानी की जरा भी कमी नहीं थी। इसकी वजह थी यहां की करुन नदी जिसमें हमेशा पानी भरा रहता था, मगर अब यह नदी सूखती जा रही है। सैटेलाइट तस्वीरों की मानें तो पिछले कुछ वर्षों में नदी में पानी का स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। साल 2019 में जब बाढ़ आई थी तो इसके पानी में तेजी से इजाफा हुआ था। ईरान के कई बड़े बांधों में अभी पानी काफी कम है और लगातार पानी छोड़ने की मांग उठ रही है ताकि धान उगाने वाले किसानों और जानवर पालने वाले लोगों की मुश्किलें हल की जा सकें।

लगातार कम होती बारिश

ईरान इस समय कई तरह की ऐसी चुनौतियों से जूझ रहा है जो पर्यावरण से जुड़ी हैं। इनमें बढ़ती गर्मी, प्रदूषण, बाढ़ और झीलों का सूख जाना शामिल है। ईरान की ऊर्जा मंत्रालय की वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार, ईरान की मुख्य नदी बेसिन में सितंबर 2020 और जुलाई 2021 के बीच हुई बारिश इसी दौरान पिछले साल हुई बारिश के मुकाबले में काफी कम थी। इन आंकड़ों के मुताबिक इस साल मार्च में हुई बारिश की पिछले 40 सालों के औसत से तुलना की गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अरविन के सेंटर फोर हाइड्रोमेट्रोलॉजी के अनुसार, साल 2021 के पहले तीन महीने उस औसत से काफी कम थे।

ईरान में साल 1983 के बाद इस साल का जनवरी महीना सबसे सूखा था। इसके बाद मार्च में भी यही हालात रहे. पिछले वर्ष नवंबर में थोड़ी बरसात हुई लेकिन अक्टूबर बीते 40 सालों में सबसे अधिक सूखा रहा। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में अनाज की एक-तिहाई खेती की भूमि के लिए सिंचाई की जरूरत है। इसलिए बारिश न होना महंगा साबित हो सकता है।

जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी वजह

येल यूनिवर्सिटी में काम कर रहे और ईरानी पर्यावरण विभाग के पूर्व उप-प्रमुख कावेह मदनी ने न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि यहां पर जलवायु परिवर्तन और सूखा, पानी की कमी की सबसे बड़ी वजह है। मगर यह समस्या दशकों से जड़ें जमा रही थीं, जिनमें बुरा प्रबंधन, खराब पर्यावरण व्यवस्था, दूरदर्शिता की कमी और पहले से इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं होना शामिल है। साल 2015 में एक पर्यावरण विशेषज्ञ ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने पानी के संकट का हल नहीं तलाशा तो फिर लाखों लोग देश को छोड़कर जा सकते हैं।

शेयर बाजार को नया मुकाम, पहली बार सेंसेक्स 54 हजार अंक के पार, निफ्टी की लंबी छलांग

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय शेयर बाजार अब एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को सेंसेक्स 54 हजार अंक के स्तर को पार कर लिया। पहली बार है जब सेंसेक्स ने ये सफलता हासिल की है। इसी के साथ निफ्टी भी नई ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स करीब 400 अंक मजबूत होकर 54,200 अंक के स्तर पर रहा। निफ्टी की बात करें तो ये 16,200 अंक के ऊपर कारोबार कर रहा था।

टाटा स्टील में सबसे ज्यादा तेजी: बीएसई इंडेक्स के 30 शेयरों में टाटा स्टील टॉप गेनर की भूमिका में है। वहीं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, पावरग्रिड, कोटक बैंक, एनटीपीसी, महिंद्रा, एलएंडटी के स्टॉक में भी जबरदस्त तेजी रही। टॉप लूजर में एयरटेल, एसबीआई, एचयूएल और सनफार्मा शामिल हैं।

मंगलवार को भी बने कई रिकॉर्ड: बीते मंगलवार को भी शेयर बाजारों में कई नए रिकॉर्ड बने। सेंसेक्स 873 अंक मजबूत होकर रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी भी पहली बार 16,000 अंक के ऊपर ठहरा। शेयर बाजार में तेजी से निवेशकों की संपत्ति 2.30 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। वहीं बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण अबतक के उच्चतम स्तर 2,40,04,664.28 पर पहुंच गया।

बाजार में तेजी की क्या है वजह

एक्सपर्ट के मुताबिक जीएसटी और निर्यात के बेहतर आंकड़ों के दम पर तेजड़ियों ने निफ्टी को 16,000 अंक के ऊपर पहुंचा दिया है। इसके अलावा घरेलू संस्थागत निवेशकों ने चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में 280 अरब रुपये की पूंजी डाली है। इस वजह से बीते कुछ समय से बाजार में तेजी देखने को मिल रही है।

चीन, इंडोनेशिया से फाइबर के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क वापस लेने की सिफारिश

नयी दिल्ली। एजेंसी

वाणिज्य मंत्रालय की इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने वित्त मंत्रालय से चीन और इंडोनेशिया से आयातित विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ) पर डंपिंग रोधी शुल्क हटाने की सिफारिश की है। इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में किया जाता है। डीजीटीआर के इस कदम की कपड़ा निर्यातकों के निकाय एईपीसी ने सराहना की है।

'एसोसिएशन ऑफ मैन मेड फाइबर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया' ने व्यापार उपचार महानिदेशालय से डंपिंग रोधी शुल्क जारी रखने का अनुरोध किया था। इसे पहले 2016 में लगाया गया था और फिर अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था। डीजीटीआर ने एक अधिसूचना में कहा, ''प्राधिकरण का मानना है कि आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क वापस लेने की सिफारिश करना उपयुक्त है।''

महानिदेशालय ने अपनी जांच में निष्कर्ष निकाला है कि चीन और इंडोनेशिया से विस्कोस स्टेपल फाइबर की डंपिंग जारी रहने की संभावना है, हालांकि, इससे घरेलू उद्योग को फिर से क्षति की आशंका इतनी मजबूत नहीं है कि लंबे समय तक शुल्क व्यवस्था को जारी रखने की आवश्यकता हो।

उसने कहा कि मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि मौजूदा मामले में डंपिंग रोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करने का कोई औचित्य नहीं है। इस फैसले का स्वागत करते हुए कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) के चेयरमैन ए शक्तिवेल ने कहा कि यह देश के कपड़ा इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। शक्तिवेल ने कहा, ''इस निर्णय से मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) क्षेत्र को अंततः आगे बढ़ने में मदद मिलेगी...।''

निजीकरण का कर रहे हैं विरोध, चार बीमा कंपनी के सभी कर्मचारी गए हड़ताल पर

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के चार साधारण बीमा कंपनियों के निजीकरण का फैसला लिया है। इसके विरोध में इन बीमा कंपनियों के कर्मचारी बुधवार को एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल पर हैं। ये कंपनियां बीमा प्रीमियम संग्रह और दावा के निपटान में नंबर वन स्थान पर हैं। इस हड़ताल को बैंक अधिकारियों के शीर्ष संगठन ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कंफेडरेशन ने भी समर्थन दिया है।

अखिल भारतीय सामान्य बीमा कर्मचारी संघ के महासचिव के. गोविंदन ने कहा कि यूनियनों ने लोकसभा में साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 को पारित किए जाने के खिलाफ एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पीएसजीआई की सभी चार कंपनियों के कर्मचारी दिन भर की हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। ये कंपनियां हैं जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया , न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड , यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ।

पेगासस जासूसी और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बीच लोकसभा ने सोमवार को बिना चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया। यह विधेयक बुधवार को चर्चा और पारित होने के लिए राज्यसभा में आने वाला है। इस विधेयक के पारित होने के बाद केंद्र सरकार किसी बीमा कंपनी में 51 प्रतिशत से कम हिस्सेदारी रख सकती है यानी उसका निजीकरण किया जा सकता है। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ (एआईआईईए) ने कहा कि इन उपायों के चलते सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की सभी चार सामान्य बीमा कंपनियों और पुनर्बीमाकर्ता जीआईसी री का निजीकरण कर सकेगी। एआईआईईए ने कहा, ''वित्त मंत्री का यह तर्क हास्यास्पद लगता है कि यह निजीकरण नहीं है, बल्कि अधिक से अधिक निजी भागीदारी की दिशा में उठाया गया कदम है।'' गौरतलब है कि पीएसजीआई कंपनियां प्रीमियम संग्रह और दावा निपटान के मामले में पहले पांच स्थान पर काबिज हैं।

GST collection:

जुलाई 2021 में जीएसटी कलेक्शन ने तोड़े रिकॉर्ड, जानिए कितनी हुई वसूली

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

जुलाई 2021 केंद्र सरकार की टैक्स संबंधी आमदनी के लिहाज से बेहतरीन महीना रहा है। केंद्र की मोदी सरकार के खजाने में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से जुलाई 2021 में 1,16,393 करोड़ रुपये आए हैं। अगर पिछले साल के जुलाई महीने से तुलना करें तो जीएसटी कलेक्शन में 33 फ़ीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें स्टेट जीएसटी के रूप में 28541 करोड़, सेंट्रल जीएसटी 22,897 करोड़ और आईजीएसटी के मद में 57,864 करोड़ रुपये शामिल है।

सेस की मदद से मिले 8000 करोड़

उएऊ में सेस की मदद से जुलाई में केंद्र सरकार को 7790 करोड़ रुपये मिले हैं जिसमें 815 करोड रुपये आयातित सामान पर लगने वाले सेस से प्राप्त हुए हैं। जीएसटी का यह कलेक्शन जुलाई के महीने में जीएसटीआर 3 फाइलिंग के जरिए हुआ है। जुलाई महीने में आयातित सामान पर वसूले गए आईजीएसटी और सेस को भी इस कलेक्शन में शामिल किया गया है।

किस राज्य की GST में कितनी हिस्सेदारी?

अगर जुलाई में राज्यों से मिले जीएसटी की हिस्सेदारी से बात करें तो महाराष्ट्र मामले में देश में अव्वल रहा है। महाराष्ट्र ने जुलाई में केंद्र सरकार को 18,900 करोड रुपये का जीएसटी दिया है। पिछले साल के जुलाई की तुलना में महाराष्ट्र के उएऊ कलेक्शन में 51 फीसदी की वृद्धि हुई है। इसके बाद तमिलनाडु ने पिछले साल की तुलना में 36 फ़ीसदी अधिक 6300 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन दिया है। गुजरात की हिस्सेदारी 7630 करोड़ के करीब रही है, जबकि उत्तर प्रदेश ने जीएसटी कलेक्शन में 6011 करोड़ रुपये का योगदान किया है। मप्र में यह 2657 करोड और ग्रोथ 16 प्रतिशत की रही। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना जैसे राज्यों की हिस्सेदारी भी जीएसटी कलेक्शन में ठीक ठाक रही है।

सबसे कम हिस्सेदारी वाले राज्य

अगर बात राज्यों के हिसाब से जीएसटी कलेक्शन की करें तो सबसे कम हिस्सेदारी लक्षद्वीप जैसे राज्य की रही है। लक्षद्वीप ने जुलाई 2021 में जीएसटी कलेक्शन में सिर्फ एक करोड़ रुपये का योगदान किया है। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह ने रू.19 करोड़, लद्दाख ने रू.13 करोड़, मिजोरम ने रू.21 करोड़, नगालैंड ने रू.28 करोड़ और मणिपुर ने रू. 37 करोड़ योगदान किया है। दमन और दीव ने जुलाई 2021 में जीएसटी में 0 योगदान किया है।

जून में जीएसटी कलेक्शन

लगातार आठ महीने तक जीएसटी कलेक्शन एक लाख करोड़ के पार रहा था लेकिन जून के महीने में यह एक लाख करोड़ के नीचे फिसल गया था। जून 2021 में जीएसटी कलेक्शन 92,849 करोड़ रुपये रहा था। इसमें ण्उएऊ से 16,424 करोड़, एउएऊ से 20,397 करोड़ और घ्उएऊ से 49,079 करोड़ रुपये शामिल थे।

सीबीआईसीः सालाना 5 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार करने वाली कंपनियां खुद प्रमाणित करेंगी जीएसटी रिटर्न

नयी दिल्ली। एजेंसी

सालाना 5 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार करने वाली कंपनियां माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के तहत अपने सालाना रिटर्न को स्वप्रमाणित कर सकेंगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कारोबारियों को राहत देते हुए कहा है कि अब उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट से अनिवार्य ऑडिट व सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। जीएसटी के तहत 2 करोड़ रुपये सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को छोड़ अन्य सभी को सालाना रिटर्न जीएसटीआर 9, 9ए दायर करना अनिवार्य है।

सीए से सत्यापन की अनिवार्यता खत्म 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर पर लागू

वहीं, 5 करोड़ से अधिक कारोबार करने वाले करदाताओं को फॉर्म जीएसटीआर 9सी के रूप में समाधान विवरण जमा कराना होता है। इस विवरण को ऑडिट के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट सत्यापित करता है। सीबीआईसी ने जीएसटी नियमों में बदलाव कर इस अनिवार्यता को खत्म कर दिया है।

उद्योगों में शोधित जल के इस्तेमाल पर 18 फीसदी जीएसटी

जीएसटी कानून से जुड़े अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) ने एक फैसले में कहा कि सीवेज वाटर के शोधन के बाद औद्योगिक इस्तेमाल करने पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। नागपुर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट ने एएआर में अपील दायर कर शोधित जल के औद्योगिक इस्तेमाल पर जीएसटी लगाने की मांग की थी। नए फैसले से पेट्रोलियम, शराब, हाउसिंग व होटल उद्योग पर असर पड़ेगा।

तम्बाकू उत्पादों पर अभी कोई अतिरिक्त शुल्क लगाये जाने का प्रस्ताव नहीं : वित्त मंत्री

नयी दिल्ली। एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि इस समय तम्बाकू उत्पादों पर कोई अतिरिक्त शुल्क लगाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्री ने एक सवाल के जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तम्बाकू उत्पादों से हर साल एकत्र औसत राजस्व लगभग 53,760 करोड़ रुपये रहा है जिसमें जीएसटी (उत्पाद एवं सेवा कर), प्रतिपूर्ति उपकर, उत्पाद शुल्क तथा राष्ट्रीय आपदा एवं आकस्मिकता शुल्क शामिल है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं पर जीएसटी की दरों को जीएसटी परिषद की सिफारिश के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अभी इस समय तम्बाकू उत्पादों पर कोई अतिरिक्त शुल्क लगाये जाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन चीजों की बढ़ाई डेडलाइन

नई दिल्ली। एजेंसी

आयकर विभाग ने मंगलवार को विभिन्न कर संबंधी अनुपालन के लिए समयसीमा बढ़ा दी। इसमें 'एक्वलाइजेशन शुल्क और Remittance से जुड़े ब्योरा शामिल हैं। 'एक्वलाइजेशन शुल्क भारत से प्रवासी सेवा प्रदाताओं को होने वाली आय पर काटा जाने वाला टीडीएस है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म -1 में इक्वलाइजेशन शुल्क ब्योरा दाखिल करने की समयसीमा 30 जून की मूल नियत तारीख से 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इसी प्रकार, अप्रैल-जून तिमाही के लिए किए गए प्रेषण (Remittance) के संबंध में अधिकृत डीलरों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले फॉर्म 15सीसी में त्रैमासिक विवरण अब 31 अगस्त तक फाइल किये जा सकते हैं। यह ब्योरा जमा करने की मूल तिथि 15 जुलाई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि करदाताओं और अन्य पक्षों ने कुछ

फॉर्मों के इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरे जाने को लेकर समस्या होने की बात कही थी। इसको देखते हुए इन फॉर्मों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरे जाने की समयसीमा बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इसके अलावा, कुछ फॉर्म की ई-फाइलिंग के लिए सुविधाओं की अनुपलब्धता को देखते हुए, सीबीडीटी ने पेंशन कोष और सरकारी संपत्ति कोष द्वारा सूचना से संबंधित फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने की नियत तारीखों को बढ़ाने का निर्णय किया है। नांगिया एंड कंपनी एलएलपी के भागीदार शैलेश कुमार ने कहा कि नये आयकर पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियों को देखते हुए करदाताओं को इस तरह की समयसीमा का अनुपालन करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और कई करदाता नियत तारीख के भीतर अनुपालन भी नहीं कर सके। उन्होंने कहा, ''कर संबंधी अनुपालन के लिये समयसीमा बढ़ाये जाने से करदाताओं को काफी राहत मिलेगी। साथ ही यह उन्हें आयकर पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण पहले की समयसीमा का पालन नहीं कर पाने को लेकर दंडात्मक कार्रवाई से भी बचाएगा।

News यू केन USE

भारत पेट्रोलियम ने वीआरके गुप्ता को सीएफओ नियुक्त किया

मुंबई। एजेंसी

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि.(बीपीसीएल) ने वीआरके गुप्ता को अपना मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) नियुक्त किया है। एन विजयगोपाल के सेवानिवृत्त होने के बाद यह नियुक्ति की गई है। वह कंपनी के निदेशक वित्त थे। उल्लेखनीय है कि बीपीसीएल के निजीकरण की तैयारी चल रही है। विजयगोपाल महारत्न कंपनी में 34 साल के करियर के बाद 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए हैं। बीपीसीएल में सीएफओ एक नया पद है। अभी तक वित्त विभाग का प्रमुख निदेशक (वित्त) होता था।

कोविड संबंधी अनुसंधान और उत्पाद विकास के लिए 1600 करोड़ रुपये आवंटित

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कोविड-19 संबंधी अनुसंधान और उत्पाद विकास के लिए 1600 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगललार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जैवप्रौद्योगिकी और इसके सार्वजनिक उपक्रम 'जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहयोग परिषद' ने कोविड संबंधी अनुसंधान और उत्पादक विकास के लिए 1300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उनके मुताबिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से 200 करोड़ रुपये और सीएसआईआर की तरफ से 104 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकरण प्रमाणपत्र शुल्क से छूट

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने बैटरी से चलने वाले वाहनों के लिये पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या उसके नवीनीकरण को लेकर शुल्क भुगतान से छूट के लिये अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने बैटरी चालित वाहनों को नये पंजीकरण चिन्हों को लेकर भी शुल्क भुगतान से छूट दी है। बयान के अनुसार देश में ई-वाहन को बढ़ावा देने के इरादे से यह कदम उठाया गया है।

अमेजन एलेक्सा से अब पूछ सकेंगे कोविड-19 जांच, टीकाकरण केंद्रों का पता

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

डिजिटल असिस्टेंट अमेजन एलेक्सा से प्रयोगकर्ता अब कोविड-19 से संबंधित सूचनाएं भी हासिल कर सकेंगे। वे एलेक्सा से नजदीकी जांच केंद्रों और टीकाकरण की जानकारी ले सकेंगे। एक बयान में कहा गया है कि 2020 में एलेक्सा से कोविड-19 संक्रमण और भारत में इसके मामलों की जानकारी प्रदान कर रही थी। अमेजन एलेक्सा को अब अपडेट किया गया है और इसमें कोविड-19 से संबंधित फीचर जोड़े गए हैं। बयान में कहा गया है कि अब एलेक्सा जांच और टीकाकरण केंद्रों की जानकारी उपलब्ध कराने के अलावा टीके की उपलब्धता के बारे में भी बताएगी। साथ ही इससे कोविड-19 हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी ली जा सकती है। बयान में कहा गया है कि ये सूचनाएं कोविन पोर्टल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट के अलावा मैपमाईइंडिया से सोर्स की गई हैं। अमेजन ने मैपमाईइंडिया से गठजोड़ किया है जिससे प्रयोगकर्ता नजदीकी कोविड-19 जांच केंद्र तथा उसकी दूरी के बारे में जानकारी पा सकेंगे।

RBI New Rules 2021

इस महीने से लागू हुआ नियम, चेक देने से पहले इस बात का रखें ध्यान, वरना होगा नुकसान

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस महीने से देश में एक जरूरी बदलाव किया, जिससे नौकरी करने वालों को बड़ा फायदा होगा एक अगस्त से नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) की सुविधा हर दिन उपलब्ध है। जबकि पहले यह सेवा बैंकों के सभी कार्य दिवसों पर ही उपलब्ध रहती थी।

क्या है NACH?

यह इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ECS) का एडवांस वर्जन है। NACH एक ऐसी बैंकिंग सुविधा है, जिसके जरिए कंपनियां और आम आदमी हर महीने के जरूरी लेनदेन को आसानी से करते हैं। एनएसीएच सर्विस को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) चलाता है। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस डीबीटी के एक लोकप्रिय और प्रमुख माध्यम के रूप में उभरा है। इससे लाभार्थियों को बड़ी संख्या में सरकारी सब्सिडी के हस्तांतरण में मदद मिली है।

छुट्टी के दिन भी क्लीयर होगा चेक

इसके तहत अब छुट्टी के दिन भी चेक क्लीयर हो जाएगा। लेकिन ऐसे में लोगों को अब सतर्क रहने की भी जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब शनिवार को जारी किया गया चेक रविवार को भी क्लीयर हो सकता है। यानी आपको चेक के क्लीयरेंस के लिए हर समय अपने खाते में बैलेंस रखना होगा, वरना चेक बाउंस हुआ तो पेनाल्टी लग सकती है। पहले चेक जारी करते समय ग्राहक सोचते थे कि यह छुट्टी के बाद ही क्लीयर होगा। लेकिन अब छुट्टी के दिन भी यह क्लीयर हो सकता है।

इसके अतिरिक्त एनएसीएच सुविधा के 24 घंटे उपलब्ध होने के और भी फायदे हैं-

बैंक में छुट्टी होने पर भी खाते से कट जाएगी ईएमआई

सुविधा के 24 घंटे उपलब्ध होने से बैंक में छुट्टी होने पर भी आपके बैंक खाते से आपकी ईएमआई कट जाएगी। म्यूचुअल फंड, लोन की ईएमआई, टेलीफोन सहित सभी बिलों का भुगतान अब बैंक की छुट्टी रहने पर भी हो जाएगा।

छुट्टी के दिन भी आएगी सैलरी

मौजूदा समय में ज्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों के खाते में सैलरी डालने के लिए नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस का इस्तेमाल करती हैं, जिससे बैंक में छुट्टी के दिन आपके अकाउंट में सैलरी नहीं आती है। लेकिन अब इस सुविधा के 24 घंटे उपलब्ध होने से, छुट्टी के दिन भी आपके खाते में पैसे जमा हो जाएंगे। एनएसीएच के जरिए बल्क लेनदेन किए जाते है। इसके जरिए सैलरी, शेयरधारकों को डिविडेंड, ब्याज और पेंशन ट्रांसफर जैसे भुगतान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बिजली, टेलीफोन व पानी के बिल का भुगतान भी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के जरिए किया जाता है। आमतौर पर इसके जरिए बल्क पेमेंट की जाती हैं।

आरबीआई के नए नियमों के कारण सभी बैंकों ने बंद किये लाखों खाते

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश के कई सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंकों ने ग्राहकों को करेंट अकाउंट बंद कर दिये है। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों को मानते हुए कई बैंकों ने लाखों की संख्या में करेंट अकाउंट बंद कर दिये गए हैं। आरबीआई के इस फैसले से लाखों एमएसएमई और छोटे कारोबारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

एसबीआई नेबंद किये 60 हजार करंट अकाउंट खाते

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंकों ने अपने बैंक में करंट अकाउंट बंद करना शुरू कर दिया है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने अपने यहां 60,000 से ज्यादा करंट अकाउंट को बंद कर दिया। बैंकों ने ई-मेल और एसएमएस के जरिये ग्राहकों को इसकी जानकारी दी है।

आरबीआई ने दिये निर्देश

निर्देशों में कहा है कि बैंक उन कस्टमर्स के करंट अकाउंट अपने यहां नहीं खोले, जिन्होंने किसी दूसरे बैंक से लोन ले रखा है। दरअसल रिजर्व बैंक बैंकों को उन अकाउंट होल्डर्स को करंट अकाउंट नहीं खोलने का निर्देश दिया है जिन्होंने दूसरे बैंक से लोन ले रखा है। ताकि, वह उन ग्राहकों के कैश पर नजर रख सकें। कई लोग जिस बैंक से लोन लेते और दूसरे बैंकों में करेंट अकाउंट खोलकर फंड्स की हेराफेरी कर रहे थे जिसपर रोक लगाने के लिए आरबीआई ने यह फैसला लिया।

क्या होता है करंट अकाउंट

करंट अकाउंट खाते में अकाउंट होल्डर्स को एक दिन में कई ट्रांजेक्शन की सहूलियत दी जाती है। आप एक ही दिन में कई बार एटीएम से पैसा निकालने से लेकर बैंक की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आपको ट्रांजेक्शन के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना है। ये बिजनेस अकाउंट होते हैं जिस पर ओवरड्राफ्ट यानी खाते में पैसा नहीं होने के बाद भी पैसा निकालने की सुविधा मिलती है। हालांकि, इसमे सेविंग अकाउंट की तरह ब्याज नहीं मिलता।

6 अगस्त को, मॉनिट्ररी पॉलिसी मीट

आरबीआई ब्याज दरों और महंगाई पर बदलेगा अपना रुख!

नयी दिल्ली। एजेंसी

3 दिनों की आरबीआई की मॉनिट्ररी पॉलिसी मीट (MPC) 4 अगस्त से शुरु हो गई है और रेट सेटिंग पैनल अपने फैसला का एलान 6 अगस्त को करेगा। इस बात की पूरी संभावना है कि आरबीआई ब्याज दरों में अपने रुख पर कोई बदलाव नहीं करेगा और यथास्थिति बरकरार रहेगी। इसकी वजह यह है कि पिछली बार की पॉलिसी मीट से अब तक इकोनॉमी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है जिससे की ब्याज दरों में बदलाव की जरुरत हो। आरबीआई का पॉलिसी रुख बना रहा है जिसमें दरों में बढ़ोतरी जैसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। मनीकंट्रोल से इस बात करने वाले अधिकांश अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आरबीआई इस मीट में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। महंगाई की ऊंची दर और इकोनॉमी में ग्रोथ की अनिश्चित स्थिति पॉलिसी मेकरों को बेहतर संकेत मिलने के लिए वेट एंड वॉच मोड में बनाए रखेगी। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि खासकर खाने-पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से आए कीमत दबाव को देखते हुए आरबीआई अपने महंगाई के अनुमान में कुछ बढ़ोतरी कर सकता है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ग्रोथ औ? महंगाई दोनों मोर्चों पर लगातार दबाव बना हुआ है। खुदरा महंगाई जून महीने में बढ़कर 6.26 फीसदी पर पहुंच गई है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते परिवहन लागत बढ़ी है। इससे महंगाई में बढ़त देखने को मिली है। जून में खुदरा महंगाई मई के तुलना में बहुत ही मामूली तौर पर घटी है लेकिन यह आरबीआई के 2-6 फीसदी के कम्फर्ट जोन से ऊपर है।

अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि ग्रोथ में रिकवरी के कुछ संकेत के बावजूद केरल में कोविड के नए मामलों के बढ़ने के चलते एक बार फिर ग्रोथ को लेकर चिंता उतपन्न हो गई है।

जानकारों का कहना है कि अगर कोविड-19 से जुड़ी अनिश्चितता जारी रहती है तो एमपीसी वेट और वॉच मोड में रहना पसंद करेगा। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि महंगाई बड़ा जोखिम बना हुआ है लेकिन एमपीसी का प्राइमरी फोकस ग्रोथ की तरफ ही रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि आरबीआई अपने ग्रोथ आउटलुक में कोई बदलाव नहीं कर सकता है लेकिन इसके महंगाई अनुमान में हमें बढ़त देखने को मिल सकती है। अन्य विशेषज्ञों ने भी कुछ इसी तरह के विचार रखे। उन्होंने कहा कि एमपीसी की बैठक, बढ़ती महंगाई,ग्रोथ पर बढ़ते दबाव और पूरी दुनिया में कोरोना महामारी से जुड़ी अनिश्चितताओं के बीच हो रही है। इस बात की संभावना है कि आरबीआई अपने दरों पर यथास्थिति बनाए रखेगा। इसके अलावा लिक्विडिटी को लेकर आरबीआई हमें कुछ कदम उठाते नजर आ सकता है।

ई-रुपी से लाभार्थी को 100 प्रतिशत लाभ सुनिश्चित हो सकेगा : उद्योग

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पर आधारित एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम 'ई-रुपी' को लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत आज कैसे आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से आगे बढ़ रहा है 'ई-रुपी' उसका एक प्रतीक है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सरकार के अलावा, अगर कोई संगठन किसी को उनके इलाज, शिक्षा या किसी अन्य काम में मदद करना चाहता है, तो वे नकद के बजाय ि्ळइ्ह वाउचर दे सकेंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि उनके द्वारा दिए गए धन का उपयोग उस कार्य के लिए किया जाए, जिसके लिए राशि दी गई थी। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि 'ई-रुपी' सफलता के नए अध्याय लिखेगा। सैकड़ों निजी अस्पतालों, उद्योग जगत, गैर सरकारी संगठनों और दूसरे संस्थानों ने भी इसको लेकर बहुत रुचि दिखाई है। उन्होंने राज्य सरकारों से भी आग्रह किया कि वह अपनी योजनाओं का सटीक और संपूर्ण लाभ सुनिश्चित करने के लिए 'ई-रुपी' का अधिक से अधिक उपयोग करें।

ई-रुपी आसान और सुरक्षित है

बता दें 'ई-रुपी' डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम है। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है। एनपीसीआई ने अपनी वेबसाइट में कहा है, 'इस निर्बाध एकमुश्त पेमेंट सिस्टम के उपयोगकर्ता ई-रुपी स्वीकार करने वाले व्यापारियों पर कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना वाउचर को भुनाने में सक्षम होंगे। ई-रुपी को लाभार्थियों के साथ एक विशिष्ट उद्देश्य या गतिविधि के लिए संगठनों या सरकार द्वारा एसएमएस या क्यूआर कोड के माध्यम से साझा किया जाएगा।' एनपीसीआई ने यह भी कहा है

कि यह कॉन्टैक्टलेस ई-रुपी आसान और सुरक्षित है, क्योंकि यह लाभार्थियों के विवरण को पूरी तरह से गोपनीय रखता है। इस वाउचर के माध्यम से पूरी लेन-देन प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेज और साथ ही विश्वसनीय है, क्योंकि आवश्यक राशि पहले से ही वाउचर में स्टोर है।

अब तक 1.78 लाख करोड़ रुपये बचा चुकी है सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि रसोई गैस सब्सिडी, राशन के पैसे और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का पैसा डीबीटी के जरिये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाकर सरकार अब तक 1.78 लाख करोड़ रुपये बचा चुकी है। प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया गया। साथ ही चोरी को रोकने में भी सफलता मिली। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को डिजिटल भुगतान के लिए ई-रुपी प्लेटफॉर्म के लॉन्चिंग मौके पर बोल रहे थे।

योजनाएं जमीनी स्तर पर बेहतर होंगी

वहीं पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि यह देश के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया के विस्तार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि आगे चलकर ई-रुपी से सरकार की विभिन्न योजनाएं जमीनी स्तर पर बेहतर हो सकेंगी। इससे सामाजिक कल्याण योजनाओं की प्रक्रिया तेज और सुगम हो सकेगी तथा साथ ही इससे कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों में निजी क्षेत्र की दक्षता बढ़ेगी।

लाभार्थी को पूरा लाभ सुनिश्चित होगा

भारतीय उद्योग जगत का मानना है कि व्यक्ति और उद्देश्य केंद्रित डिजिटल भुगतान समाधान ई-रुपी से लक्षित लाभार्थी को पूरा लाभ सुनिश्चित हो सकेगा और उसमें किसी तरह की अपवंचना नहीं हो सकेगी। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष टी वी नरेंद्रन ने कहा कि इस भुगतान तंत्र के जरिये सरकार नागरिकों को मौद्रिक समर्थन बिना मध्यवर्ती इकाइयों के प्रदान कर सकेगी। उन्होंने कहा कि वाउचर प्रणाली से सभी लाभार्थियों (फीचर फोन के प्रयोगकर्ताओं सहित) को लाभ होगा। यह कॉरपोरेट के लिए भी एक अच्छा माध्यम साबित होगा। फिनटेक फर्म एफआईएस में सीआरओ भरत पांचाल ने कहा, 'नया डिजिटल भुगतान मोड ई-रुपी मूल रूप से एक प्रीपेड वाउचर है, जिसे मोबाइल नंबर और पहचान की पुष्टि के बाद सीधे नागरिकों को जारी किया जा सकता है। ई-रुपी वाउचर को क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग-आधारित ई-वाउचर के रूप में लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, 'लाभार्थी सेवा प्रदाता पर कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना वाउचर को भुना सकता है। यह उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी उपकरण होगा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए निजी नहीं हैं, फिर भी सरकार यूपीआई द्वारा संचालित प्रीपेड ई-वाउचर के रूप में 'लीक-प्रूफ तरीके' से नागरिकों को सीधे डिजिटल रूप में मौद्रिक सहायता प्रदान कर सकती है।

कोविड-19 : अभी खत्म नहीं हुई है दूसरी लहर

आठ राज्यों में अभी भी 'आर-वैल्यू' ज्यादा, सरकार ने किया आगाह

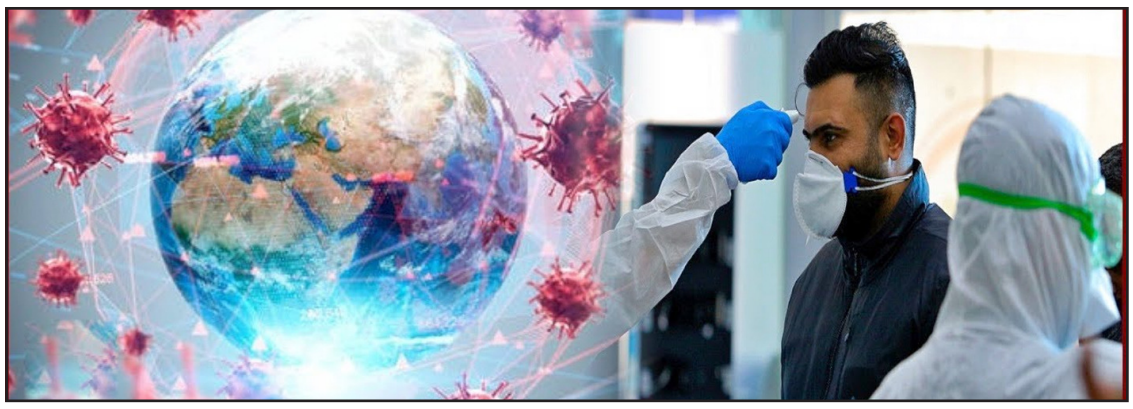

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कोविड-19 महामारी देश में अभी खत्म नहीं हुई है। दूसरी लहर अब भी बरकरार है और अंदेशा तीसरी लहर का है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, वायरस के प्रसार में फिर से तेजी के संकेत मिल रहे हैं। कोरोना के प्रसार को दर्शाने वाले रिप्रोडक्टिव रेट आठ राज्यों में एक से अधिक हैं। यह दर कुछ समय पूर्व 0.6 पर पहुंच गई थी तथा पिछले महीने 0.8 हुई और अब बढ़कर 1.2 हो गई है। तीन राज्यों में यह और भी अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल एवं नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में आर नंबर सबसे ज्यादा 1.4 रिप्रोडक्टिव रेट है जबकि लक्षद्वीप में 1.3 है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, गोवा, झारखंड, नगालैंड में यह 1 तथा केरल में और पुडुचेरी में 1.1 है।

देश में दूसरी लहर अभी भी पूरी तरह से नहीं हुई है खत्म

लव अग्रवाल ने कहा कि वैश्विक महामारी खत्म होने से अभी बहुत दूर है। जहां तक भारत की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर अब भी खत्म नहीं हुई है। दुनियाभर से कोविड-19 के दैनिक नए मामले अब भी बहुत ज्यादा हैं, जहां संक्रमण के हर दिन 47 हजार से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 44 जिलों में 2 अगस्त को समाप्त हो रहे हफ्ते में कोरोना वायरस की साप्ताहिक संक्रमण दर 10 प्रतिशत से अधिक है।

क्या होता है रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव रेट?

यदि यह एक से नीचे होता है तो यह माना जाता है कि रोग नियंत्रण में है। एक से अधिक होने पर रोग के तेज प्रसार का संकेत मिलता है। रिप्रोडक्टिव रेट या आर वैल्यू यह बताता है कि कोई रोग कितना संक्रामक है यानी एक मामले से कितने और मामले फैल सकते हैं, इसकी संख्या दर्शाता है।

8 राज्यों के 18 जिलों ने बढ़ाई चिंता

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश समेत छह राज्यों के 18 जिलों में पिछले चार हफ्तों में कोविड के नये दैनिक मामले बढ़ते दिख रहे हैं। यह चिंता का विषय है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले हफ्ते, कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों में से 49.85 प्रतिशत मामले केरल से सामने आए।

दूसरी लहर अभी भी नहीं हुई है खत्म

लव अग्रवाल ने कहा कि वैश्विक महामारी खत्म होने से अभी बहुत दूर है। जहां तक भारत की बात है तो दूसरी लहर अब भी खत्म नहीं हुई है। दुनियाभर से कोविड-19 के दैनिक नये मामले अब भी बहुत ज्यादा हैं, जहां संक्रमण के हर दिन 47 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं।

हर वायरस और वेरिएंट से बचाएगी 'सुपर वैक्सीन'

एक टीका तय करेगा इंसानों का भविष्य

लंदन। एजेंसी

ब्रिटेन में एक ओर जहां कोरोना प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है तो वहीं वैक्सीन लगवा चुके लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि महामारी का अंत अब नजदीक है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि महामारी को पूरी तरह से खत्म होने में अभी काफी समय लगेगा। न्यूयॉर्क स्थित प्र्ल्ह्ह ्रम्म्हो इदराम्ू के को-फाउंडर टेड शेंकेलबर्ग के मुताबिक बड़े शहरों के पर्यावरण और भाग दौड़ वाली जीवनशैली के चलते कोरोना वायरस परिवार के अगले सदस्य का प्रकोप 'निश्चित' है।

कोई नहीं चाहता महामारी की वापसी

उन्होंने चेतावनी दी कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो महामारी के लिए तैयार है। ऐसे में क्या आने वाले समय में कोई यूनिवर्सल वैक्सीन की सिंगल डोज कोरोना वायरस के सभी सदस्यों और कोविड-19 के सभी वेरिएंट से सुरक्षा दे पाएगी? मौजूदा वायरस ने जो तबाही मचाई है उसे कोई भी दोहराना नहीं चाहता। पूरी दुनिया के लिए 'एक कोरोना वायरस वैक्सीन' बड़ा सवाल है।

नए स्ट्रेन बढ़ा रहे वैज्ञानिकों की मुश्किलें

दुनिया अभी भी SARS-CoV-2 के लिए सही वैक्सीन हासिल करने की कोशिश कर रही है। इसके नए स्ट्रेन भी सामने आ रहे हैं जो वैज्ञानिकों के लिए लगातार चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। हालांकि कोरोना वायरस परिवार के सभी सदस्यों में कुछ समान लक्षण होने के कारण वैज्ञानिकों ने 'सुपर वैक्सीन' के लिए रिसर्च शुरू कर दी है।

वैज्ञानिकों ने शुरू की रिसर्च

इस साल की शुरुआत में CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) ने महामारी के भविष्य के जोखिम को कम करने या खत्म करने के लिए 2.5 बिलियन पाउंड की एक पांच साल की योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत SARS-CoV-2 के सभी वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने के लिए अमेरिकी कंपनी VBI Vaccines के साथ 24 मिलियन पाउंड की पार्टनरशिप की गई थी। CEPI 'All-in-One' टीकों पर काम करने वाले वैज्ञानिकों से प्रस्ताव मांग रही है।

हर कोरोना वायरस से बचाएगी All-in-One वैक्सीन

All-in-One वैक्सीन आने वाले समय में कोरोना वायरस से व्यापाक सुरक्षा दे सकती है। वैज्ञानिकों का विश्वास है 'सुपर वैक्सीन' किसी भी ज्ञात कोरोना वायरस या किसी जानवर में छिपे वायरस पर कारगर होगी। यूनिवर्सल वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिकों को सभी कोरोना वायरस के बीच एक जैसी विशेषताओं और संरचनाओं पर फोकस करना होगा।

श्रावण मास चल रहा है, जानिए महीने भर के शुभ उपाय, खूब मिलेगा यश, धन और सुख

श्रावण मास चल रहा है...आइए जानते हैं इस महीने भगवान भोलेनाथ को कैसे करें प्रसन्न....सरल उपायों से खूब मिलेगा यश,धन और सफलता....प्रेम,शांति और समृद्धि....

सावन में रोज शिवलिंग पर केसर मिला दूध चढ़ाएं। इससे विवाह की बाधाएं दूर हो जाएंगी।

घर में नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए सावन में रोज सुबह घर में गंगाजल का छिड़काव करें और धूप जलाएं।

सावन में गरीबों को भोजन कराने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। इससे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती और साथ ही पितरों को भी शांति मिलती है।

सावन में रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निपट कर मंदिर या फिर घर में ही भगवान शिव का जलाभिषेक करें। इसके साथ ही 'ऊं नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें।

आमदनी बढ़ाने के लिए सावन के महीने में किसी भी दिन घर में पारद शिवलिंग की स्थापना करें और उसकी यथा विधि पूजन करें। इस दौरान इस मंत्र का 108 बार जाप करें। 'ऐं ह्रीं श्रीं ऊं नमः शिवायः श्रीं ह्रीं ऐं'

प्रत्येक मंत्र के साथ बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। बिल्वपत्र के तीनों दलों पर लाल चंदन से क्रमशः ऐं, ह्री, श्रीं लिखें। अंतिम 108 वां बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद निकाल लें और इसे घर के पूजन स्थान पर रखकर प्रतिदिन पूजा करें।

सावन में गेहूं के आटे से 11 शिवलिंग बनाएं और प्रत्येक शिवलिंग का शिव महिम्न स्त्रोत से 11 बार जलाभिषेक करें।

सावन के सोमवार को पानी में दूध व काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करने से बीमारियां दूर होती हैं। अभिषेक के लिए तांबे के बर्तन को छोड़कर किसी भी धातु का उपयोग किया जा सकता है। सावन में किसी नदी या तालाब में जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं और साथ ही साथ मन में भगवान शिव का ध्यान करें इससे आपको मनचाहे फल की प्राप्ति होगी।

सावन के महीने में 3 राशियां होती हैं भाग्यशाली, भोलेनाथ के मिलते हैं भरपूर आशीष

श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व होता है क्योंकि शिव मंत्रों के जाप से जातकों के जीवन में बुरे ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है।

सावन के महीने में सोमवार व्रत और शिवलिंग का जलाभिषेक करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाता है। सावन का महीना भगवान शिव बहुत ही प्रिय है और जो शिवभक्त इस पवित्र माह में शिवजी की पूजा मन से करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। आइए जानते हैं कि सावन के पवित्र महीने में कौन सी तीन राशियां है जिस पर हमेशा भगवान शिव की कृपा रहती है।

मेष

मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगलदेव होते हैं। भगवान भोलेनाथ को मेष राशि बहुत ही प्रिय होती है। उनकी शुभ दृष्टि हमेशा इस पर रहती है। मेष राशि के जातकों पर हमेशा शिव की कृपा रहने से इस राशि के जातकों के जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। इस राशि के जातकों को शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। मेष राशि के जातकों पर भगवान शिव की कृपा होने से नौकरी और व्यापार में हमेशा तरक्की होती रहती है। मेष राशि वाले जातक किसी भी काम में थोड़ी से भी मेहनत कर देते हैं तो वह काम जरूर सफल हो जाता है। क्योंकि इन पर शिवजी की विशेष कृपा रहती है। ऐसे में भगवान शिव को और अधिक प्रसन्न करने के लिए सावन के महीने में इस राशि के जातकों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना चाहिए।

मकर

मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। मकर राशि भी शिवजी की प्रिय राशियों में से एक है। इस राशि पर शनि और शिव दोनों की कृपा होती है। जब भी इस राशि के जातकों पर किसी प्रकार की विपदा आती है तो उस समय भगवान शिव आने वाली कठिनाइओं को कम कर देते हैं। सावन के महीने में इस राशि के जातकों को शिव आराधना जरूर करनी चाहिए। इस राशि के जातकों के लिए शिव पूजा बहुत ही लाभकारी और शुभफलदायी मानी गई है। मकर राशि के जातकों को शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के अलावा बेलपत्र भी अर्पित करना चाहिए। वहीं पूजा करते समय महामृत्युंजय का जाप भी करना चाहिए। मकर राशि के जातकों को शिवजी बहुत ही भाग्यशाली बनाते हैं।

कुंभ

मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं। शनिदेव दो-दो राशियों के स्वामी माने जाते हैं। शनि की इस राशि पर भी शिव की कृपा हमेशा बरसती है। सावन के महीने में भी कुंभ राशि के जातकों को शिव आराधना करनी चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए सावन के महीने में ॐ नमः शिवाय का जाप सभी तरह के कष्टों को दूर करने के लिए शुभ रहता है। सावन के महीने में इस राशि के जातकों के लिए दान करना शुभ रहेगा।

अगस्त माह की 2 एकादशी कौन सी हैं, जानिए महत्व

अगस्त माह में बहुत ही खास 2 एकादशी आ रही है। एक एकादशी जहां सभी पापों का नाश करने में सक्षम है, वहीं दूसरी एकादशी संतान देने वाली मानी गई है।

इस वर्ष श्रावण मास कामिका और पुत्रदा एकादशी व्रत मनाया जाएगा। कामिका एकादशी का यह व्रत लोक हित के लिए बहुत जरूरी है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। यह एकादशी 4 अगस्त 2021, बुधवार को मनाई जाएगी। पौराणिक ग्रंथों में इस एकादशी का इतना महत्व है कि इसकी कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है।

इस दिन शंख, चक्र, गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन करने का विधान है। इस एकादशी के दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन इन नामों से पूजन करने से गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से जो मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल ग्रहण के समय काशी में स्नान करने, समुद्र, वन सहित पृथ्वी दान करने से भी प्राप्त नहीं होता वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है।

शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। यह पूजन सभी पापों के नाश करने में सक्षम है।

अगस्त माह में दूसरा एकादशी का व्रत 18 अगस्त 2021, बुधवार मनाया जाएगा। इस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। यह दिन संतान प्राप्ति के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन संतान प्राप्ति की कामना के लिए भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा भी की जाती है।

यदि पूरे मन से निःसंतान दंपति यह व्रत करता हैं तो उन्हें संतान सुख अवश्य मिलता है। यह एकादशी संतान प्राप्ति तथा उसके दीघार्यु जीवन के लिए बहुत महत्व की मानी गई है।

लग्न से जानिए कौन से ज्योतिर्लिंग शिव की पूजा शुभ है आपके लिए

श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा, अर्चना, भक्ति करने से अनन्य फल की प्राप्ति होती है, पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं.. 12 ही राशि और 12 ही लग्न हैं। जन्म लग्न और राशि के अनुसार शिव पूजा करना शुभ फलदायी होता है।

मेष लग्न और राशि - ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना करें।
वृषभ लग्न और राशि - बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की आराधना करें।
मिथुन लग्न और राशि - त्र्यम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना करें।
कर्क लग्न और राशि - भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की आराधना करें।
सिंह लग्न और राशि - महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना करें।
कन्या लग्न और राशि - घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना करें।
तुला लग्न और राशि - रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना करें।
वृश्चिक लग्न और राशि - नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना करें।
धनु लग्न और राशि - सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की आराधना करें।
मकर लग्न और राशि - मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की आराधना करें।
कुंभ लग्न और राशि - केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की आराधना करें।
मीन लग्न और राशि - विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की आराधना करें।

रोजगार चाहिए तो मंगलवार को अपनाएं ये 3 खास उपाय

नौकरी-रोजगार की तलाश में हैं और हर तरफ से निराश हो गए हैं तो इस मंगलवार के दिन आजमाएं यह 3 उपाय।

पहला उपाय- आप बेरोजगार है या आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आप मंदिर में बैठकर 11 मंगलवार तक सुंदरकांड का पाठ करें। यह पाठ शुरू करने के लिए हनुमान जयंती के दिन चुनेंगे तो अतिउत्तम रहेगा।

दूसरा उपाय- यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं तो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाएं, तो जेब में लाल रूमाल या कोई लाल कपड़ा रखें लेकिन यह कपड़ा या रूमाल बजरंगबली के चरणों में रखा हुआ होना चाहिए।

तीसरा उपाय- प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रति मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं। हो सके तो पांच शनिवार या मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को पान विशेष पसंद है। अतः 11 मंगलवार उन्हें पान और पूरी सुपारी अलग से चढ़ाएं।

लंदन और बहरीन के लोग उठाएंगे भारतीय ड्रैगन फ्रूट का लुत्फ, इन दो राज्यों से पहली खेप रवाना

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

अब लंदन और बहरीन के लोग भारतीय ड्रैगन फ्रूट का लुत्फ उठाएंगे। गुजरात और पश्चिम बंगाल के किसानों के फाइबर और खनिज पदार्थों से समृद्ध 'ड्रैगन फ्रूट' या कमलम (Kamalam) की खेप को लंदन और बहरीन भेजा गया है। भारत से पहली बार लंदन और बहरीन को ड्रैगन फ्रूट का निर्यात किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

मंत्रालय ने कहा कि लंदन को निर्यात की जाने वाली खेप को गुजरात के कच्छ) क्षेत्र के किसानों से लिया गया था, जबकि बहरीन की खेप पश्चिम मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) के किसानों से मंगवाई गई थी। ड्रैगन फ्रूट की तीन मुख्य किस्में हैं-'व्हाइट फ्लेश विथ पिंक स्किन', 'रेड फ्लेश विथ पिंक स्किन' और 'व्हाइट फ्लेश विथ येलो स्किन'।

यह फल ज्यादातर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उगाया जाता है। पश्चिम बंगाल इस विदेशी फल की खेती के लिहाज से नया क्षेत्र है। इस फल का उत्पादन करने वाले मुख्य देशों में मलेशिया, थाइलैंड, फिलीपींस, अमेरिका और वियतनाम शामिल हैं। ये देश भारत के लिए प्रमुख प्रतिस्पर्धी हैं। इस साल की शुरुआत में गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम रखने का फैसला किया था। इसका उत्पादन राज्य के कच्छ, नवसारी और सौराष्ट्र के कई इलाकों में होता है। गुजरात सरकार का मानना था कि ड्रैगन फ्रूट नाम से इसका संबंध चीन से होने का संकेत मिलता है। इस साल जून में महाराष्ट्र ने ड्रैगन फ्रूट का निर्यात दुबई को किया था। भारत में ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ था। पिछले कुछ सालों में देश में इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। देश के कई राज्यों में इसका उत्पादन हो रहा है।

भारत ने चीन के फार्मा रसायन की डंपिंग रोधी जांच शुरू की

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत ने चीन से आयातित रसायन के खिलाफ डंपिंग रोधी जांच शुरू कर दी है। इस रसायन का उपयोग फार्मा उद्योग में होता है। यह जांच भारतीय दवा कंपनी आर्च फार्मा लैब्स द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद शुरू की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) चीन से 'एटीएस-8' की कथित डंपिंग की जांच कर रहा है। भारतीय दवा कंपनी आर्च फार्मा लैब्स ने डीजीटीआर के समक्ष अपनी शिकायत में चीन से आयात किये जाने वाले रसायन के संबंध में डंपिंग रोधी जांच शुरू करने की मांग की थी। कंपनी का आरोप है कि रसायन की डंपिंग ने भारतीय दवा उद्योग को प्रभावित किया है। एक अधिसूचना के अनुसार घरेलू दवा उद्योग द्वारा उचित रूप से लिखित शिकायत और रसायन के बारे में पेश शुरुआती सबूतों के आधार पर डीजीटीआर ने जांच शुरू कर दी है। डीजीटीआर ने कहा कि यदि में जांच यह पाया गया कि रसायन से घरेलू दवा उद्योग को नुकसान हुआ है, तो वह चीन से आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करेगा। वित्त मंत्रालय हालांकि यह शुल्क लगाने का अंतिम निर्णय लेता है। गौरतलब है कि चीन से आयात किया जाना वाला रसायन एटोरवास्टेटिन एपीआई के निर्माण के लिए प्रमुख कच्चा माल है।

वर्ष 2030 तक चरम पर होगा कार्बन उत्सर्जन

हांगकांग। एजेंसी

चीन ने एक बार फिर दोहराया है कि उसके यहां 2030 तक कार्बन उत्सर्जन अपने चरम पर पहुंचेगा और उसके बाद ही उसमें कमी आएगी। साथ ही उसने कहा कि वह इसमें कमी लाने के संबंध में जल्द ही विस्तृत योजना की घोषणा करेगा। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन का कहना है कि चीन जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में और सहयोग करे। जलवायु परिवर्तन पर देश के दूत शिआ जेनहुआ ने एक ऑनलाइन वेबिनार में कहा कि चीन जल्द ही कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए योजना जारी करेगा और इस साल के अंत में स्कॉटलैंड, ग्लासगो में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन में उसके बारे में विस्तार से बताएगा। चीन पहले भी कह चुका है कि 2030 में उसके यहां कार्बन उत्सर्जन चरम पर होगा और फिर नीचे आएगा, वह कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने (कार्बन न्यूट्रालिटी) के लक्ष्य को 2060 तक प्राप्त करेगा। दुनिया के सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक ने दलील दी है कि वह अभी भी विकासशील अर्थव्यवस्था है और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में उसे विकसित देशों की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। दुनिया भर के नेता और जलवायु परिवर्तन पर ठोस कदम उठाने की वकालन करने वाले 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी) के लिए नवंबर में ग्लासगो में एकत्र होंगे। इस सम्मेलन में सभी देश एकजुट होकर कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और जलवायु परिवर्तन में धरती के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोके रखने पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि जलवायु परिवर्तन के भीषण परिणामों से बचा जा सके।

मारोठिया बाजार के नवनियुक्त संघ अध्यक्ष का जन्मदिन मनाया गया

इंदौर। विशेष प्रतिनिधि

मारोठिया बाजार व्यापारी संघ से जुड़े समाजसेवी नितिन सहजवानी के नेतृत्व में मनाया गया वहीं संघ के अध्यक्ष विशाल शर्मा जी को कई व्यापारियों शुभकामनाएं दी मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन संघर्ष संघर्ष समिति के नगर अध्यक्ष संतोष वाधवानी जी ने भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना व शुभकामनाएं दी वही सहजवानी ने कहा कि नवनियुक्त अध्यक्ष के कार्यकाल में बाजार एक नई दिशा की ओर अग्रसर होगा

News यू केन USE

शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 18 पैसे चढ़ा

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

घरेलू शेयर बाजार में मजबूती और अमेरिकी मुद्रा की कमजोरी के चलते रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 18 पैसे चढ़कर 74.10 के स्तर पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में घरेलू मुद्रा डॉलर के मुकाबले 74.16 पर खुली, और बढ़त दर्ज करते हुए 74.10 पर पहुंच गई, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 18 पैसे की बढ़त दर्शाता है। रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 74.28 पर बंद हुआ था। इसबीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.06 प्रतिशत गिरकर 92.02 पर आ गया। मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि निवेशकों की नजर इस सप्ताह होने वाली भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति बैठक के संकेतों पर है।

जून में भारत का कच्चे इस्पात का उत्पादन 21.4 प्रतिशत बढ़कर 94 लाख टन रहा

नयी दिल्ली। एजेंसी

वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार जून में भारत का कच्चे इस्पात का उत्पादन सालाना आधार पर 21.4 प्रतिशत बढ़कर 94 लाख टन हो गया। एक साल पहले इसी महीने में भारत का कच्चे इस्पात का उत्पादन 69 लाख टन था। वैश्विक उद्योग निकाय ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा, 'वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (वर्ल्डस्टील) को रिपोर्ट करने वाले 64 देशों का उत्पादन जून 2021 में 16.79 करोड़ टन था, जो जून 2020 की तुलना में 11.6 प्रतिशत अधिक है।' चीन जून में इस्पात के उत्पादन में शीर्ष पर बना रहा, पिछले साल के इसी महीने में 9.16 करोड़ टन की तुलना में इस साल जून महीने के दौरान उसका उत्पादन सालाना आधार पर 1.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 9.39 करोड़ टन रहा। जापान का इस्पात उत्पादन जून 2020 में 56 लाख टन से बढ़कर 81 लाख टन हो गया। अमेरिका ने जून महीने में 71 लाख टन इस्पात का उत्पादन किया। जून 2020 में उसका उत्पादन 47 लाख टन था।

सरकार का ध्यान पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क तंत्र को बढ़ावा देने पर : गोयल

मुंबई। एजेंसी

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि सरकार का ध्यान देश में पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क तंत्र को बढ़ावा देने पर है। गोयल ने कहा कि सरकार विरासत प्रणालियों से नए आविष्कारों और ज्ञान को वैश्विक मंचो पर लाना चाहती है। गोयल ने पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक (सीजीपीडीटी) की समीक्षा बैठक में कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और जीआई प्रणाली तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे देश में नवाचार, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा मिलेगा। देश को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में बनाने के लिए सरकार 2014 से प्रयास कर रही है।'' उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग और व्यक्तिगत महिलाओं द्वारा दस्तावेज दाखिल करने को लेकर शुल्क में 80 फीसदी की छूट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इन सभी कदमों से देश में अनुसंधान, नवाचार, विकास और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिलेगा।

मॉडर्न ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूशन्स में भारतीय शिक्षण मंडल के द्वारा 'व्यास पूजन महोत्सव' कार्यक्रम सम्पन्न

इंदौर। विशेष प्रतिनिधि

भारतीय शिक्षण मंडल, मालवा प्रांत व मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा 'व्यास पूजन महोत्सव' का आयोजन आज दिनांक 4 अगस्त को सुबह 11 बजे, गूगल प्लेटफार्म पर आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय शिक्षण मंडल के शालेय प्रमुख एवं पालक अधिकारी मध्य क्षेत्र श्री मदन खत्री जी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मॉडर्न ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूसन्श के समूह निदेशक एवं अभाविप के इंदौर महानगर अध्यक्ष डॉ. पुनीत कुमार द्विवेदी ने की। भारतीय शिक्षण मंडल के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य श्री नरेश मिश्रा जी ने भारतीय शिक्षण मंडल के विभिन्न कार्यों एवं आयामों के बारे में जानकारी दी। मुख्य अतिथि श्री मदन खत्री जी ने शिक्षक-शिक्षार्थी संबंधों की प्रासंगिकता को लेकर वेदकाल से वर्तमान समय तक के परिवर्तनों की चर्चा की। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉ. पुनीत द्विवेदी द्वारा व्यक्ति निर्माण के द्वारा समाज निर्माण हेतु शिक्षक के कर्तव्यों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के सहसंयोजक द्वय श्री हर्षवर्धन जैन जी एवं डॉ. वैशाली वाईकर ने कार्यक्रम का सफल संयोजन एवं संचालन किया। इस एक घंटे का कार्यक्रम में मॉडर्न ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूट्स के लगभग 85 शिक्षक एवं विद्यार्थी प्रतिभागी जुड़े रहे।

अब इंदौर में मिलेगा इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक स्कूटर एथर

एथर एनर्जी ने इंदौर में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला

कासलीवाल ग्रुप और एथर एनर्जी ने इंदौर में एबी रोड पर उद्घाटन किया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत के पहले इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता, एथर एनर्जी ने कासलीवाल ग्रुप के साथ इंदौर में एबी रोड पर अपने नए रिटेल आउटलेट - एथर स्पेस - का उद्घाटन किया। एथर 450एक्स भारत का सबसे तेज

और स्मार्ट स्कूटर है, और यह स्कूटर एथर 450 प्लस के साथ एथर स्पेस में टेस्ट राइड और विक्रय के लिए उपलब्ध रहेगा। पिछले कुछ वर्षों में, मध्य प्रदेश सरकार ने ईवी को अपनाने में तेजी लाने के लिए कई नीतियां बनाई हैं जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर 25इ तक सब्सिडी देना, पहले 22,500 इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स के लिए वाहन पंजीकरण में छूट, और नगर निगम संचालित पार्किंग स्थलों में सभी ईवी वाहनों को मुफ्त पार्किंग सुविधा।इन नीतियों से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी आएगी। इंदौर में एथर स्पेस खोलने के पीछे शहर के उपभोक्ताओं की भारी मांग से मिली प्रेरणा है। यह मांग जनवरी 2020 में एथर 450एक्स और450 प्लस के लॉन्च के बाद बढ़ती हुई देखी गई हैं।

एथर स्पेस ईवी मालिकों के लिए संपूर्ण सेवा और सहायता के साथ अद्वितीय स्वामित्व अनुभव प्रदान करने के लिए तैयार है। नया एथर स्पेस ग्राहकों को वाहन के हर पहलू के बारे में जानने का अवसर प्रदान करेगा और डिस्प्ले पर स्ट्रिप्ड-नेयर यूनिट के साथ विभिन्न पुर्जों का पूरा ओवरव्यू दिखाएगा। यह मध्य प्रदेश में एथर एनर्जी का पहला एक्सपीरियंस सेंटर है। इस साल की शुरुआत में, एथर ने मुंबई, पुणे, हैदराबाद, कोच्चि, अहमदाबाद, नई दिल्ली, त्रिची, विशाखापत्तनम, जयपुर और कोझीकोड सहित कई शहरों में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है।

एथर एनर्जी उन कुछ ओईएम में शामिल है जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश करती हैं। कंपनी ने छह फास्ट-चार्जिंग पॉइंट, एथर ग्रिड स्थापित किए हैं, जो भंवर कुआं, अन्नपूर्णा, रेस कोर्स रोड, नंदा नगर, राज मोहल्ला और एबी रोड पर हैं। सभी एथर ग्रिड स्थानों को रणनीतिक रूप से शहर के प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्ध किया गया है ताकि पूरे इंदौर में ईवी मालिकों के लिए ये आसानी से उपलब्ध हो सके। एथर एनर्जी ने शहर में चार्जिंग नेटवर्क को मजबूती देने के लिए 8-10 और चार्जिंग पॉइंट जोड़ने की योजना बनाई है, ताकि ईवी मालिकों के लिए सुगम और तनाव मुक्त राइड प्रदान की जा सके। एथर एनर्जी ग्राहकों को उनके अपार्टमेंट और बिल्डिंग में घरेलू चार्जिंग सॉल्यूशंस स्थापित करने में भी मदद करती है। फेम (ईस-2) संशोधन के बाद, इंदौर में एथर 450एक्स की एक्स-शोरूम कीमत 146,926 रुपये है और एथर 450 प्लस की एक्स-शोरूम कीमत 127,916 रुपये है।

चीफ बिजनेस ऑफिसर, एथर एनर्जी रवनीत फोकेला ने बताया कि एथर 450एक्स के लॉन्च के बाद से इंदौर से टेस्ट राइड के अनुरोध और प्री-ऑर्डर लगातार आ रहे हैं। फेम 2 संशोधन के साथ, आने वाले दिनों में ईवी मोबिलिटी में बदलाव अधिक मांग पैदा करेगा। नया एथर स्पेस इंदौर में हमारे उभरते हुए ग्राहक आधार को शानदार अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है। इंदौर के बाद, वर्ष के अंत तक भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य 3-4 शहरों में हमारी उपस्थिति दर्ज होने की उम्मीद है।

कासलीवाल ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आराध्य कासलीवाल ने बताया कि भविष्य सामने मौजूद है और बाइकिंग का नया युग - एथर 450एक्स अब इंदौर में शुरू हो चुका है। हमें खुशी है कि हम इंदौर में स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रदान करने के लिए देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर टेक्नोलॉजी के लीडर - एथर एनर्जी के साथ जुड़ रहे हैं। हम इंदौर की जनता को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा दिखाने ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और हम अपने ग्राहकों को एथर एनर्जी के साथ उनकी यात्रा में एक बाधारहित और यादगार अनुभव देने जा रहे हैं।

देश का पहला इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक वाहन

भारत के पहले इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं में से एक, एथर एनर्जी की स्थापना 2013 में आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्रों, तरुण मेहता और स्वप्निल जैन ने की थी। एथर ने एक व्यापक सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क, एथर ग्रिड भी स्थापित किया है, जिसे भारत में डिजाइन किया गया है और बनाया गया है। पूरे भारत में 142 चार्जिंग पॉइंट्स के साथ, एथर ग्रिड देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सबसे बड़े फास्ट-चार्जिंग नेटवर्क में से एक है। कंपनी की प्रोडक्ट लाइन ने डिजाइन, ऑटोमोटिव और टेक्नोलॉजी श्रेणियों में 37 पुरस्कार जीते हैं। 58 भारतीय और अंतरराष्ट्रीय पेटेंट एप्लिकेशंस, 109 ट्रेडमार्कों तथा 118 भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन पंजीकरणों के साथ एथर एनर्जी का लक्ष्य उपभोक्ताओं को सबसे अच्छा स्वामित्व अनुभव प्रदान करना है। एथर एनर्जी वर्तमान में बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, जयपुर, कोच्चि, अहमदाबाद, मुंबई, मैसूर और हुबली सहित 22 शहरों में काम कर रहा है।

एथर 450एक्स के बारे में

एथर 450एक्स अपनी श्रेणी में सबसे तेज और सबसे स्मार्ट स्कूटरों में से एक है, और यह चार रंगों में उपलब्ध है: लिमिटेड-एडिशन सीरीज 1 के साथ ग्रे, ग्रीन और सफेद। स्कूटर 6किलोवाट पीएमएसएम मोटर, 2.9 किलो वाट घंटे की लिथियम-आयन बैटरी से संचालित है, और इसमें 4 राइडिंग मोड मिलता है। ईको, राइड और स्पोर्ट के अलावा, एथर एनर्जी ने एक नया हाई-परफॉर्मेंस मोड 'वार्प' पेश किया है। एथर 450एक्स, वार्प मोड में केवल 3.3 सेकंड में 0 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है, जो इसे 125सीसी श्रेणी का सबसे तेज स्कूटर बनाता है और यह शहर के ट्रैफिक में चलने के लिए सही विकल्प है। एथर 450एक्स 1.5 किमी प्रति मिनट की रफ्तार से फास्ट-चार्ज कर सकता है, जो इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कैटेगरी में सबसे तेज चार्जिंग रेट है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक स्कूटर में 4जी सिम कार्ड और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, जिससे राइडर्स टचस्क्रीन डैशबोर्ड से फोन कॉल कर सकते हैं और म्यूजिक चला सकते हैं। 7'टचस्क्रीन डैशबोर्ड में 16एम की कलर डेप्थ और एक स्नैपड्रैगन क्वाड-कोर प्रोसेसर है। एथर 450एक्स गूगल मैप नेविगेशन, ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक्स, और अन्य अनूठी विशेषताएं जैसे ओवर-द-एयर अपडेट, ऑटो इंडिकेटर ऑफ और गाइड-मी-होम लाइट देने के लिए एंड्रॉइड ओपन सोर्स का उपयोग करता है।

अब हाइवे पर धूम मचाने की तैयारी में रिलांयस

नई दिल्ली। एजेंसी

देश के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की नजर पर अब देश के हाइवेज पर है। रिलायंस और ब्रिटेन की कंपनी बीपी का जॉइंट वेंचर रिलायंस बीपी मोबिलिटी हाइवेज पर स्थित अपने पेट्रोल पंपों पर रीटेल आउटलेट्स खोलने की योजना बना रही है। इनमें कन्वीनियंस स्टोर्स और फूड जॉइंट्स शामिल हैं।

सूत्रों के मुताबिक रिलायंस रीटेल इन आउटलेट्स को ऑपरेट करेगी। इसमें स्मार्ट पॉइंट कन्वीनियंस स्टोर्स, डिजिटल स्टोर्स, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स, कैफे और अन्य फूड एंड बेवरेजेज आउटलेट्स शामिल होंगे। रिलायंस बीपी मोबिलिटी साथ ही दूसरी फूड एंड बेवरेजेज चेंस के साथ भी बातचीत कर रही है। उन्हें कंपनी की प्रॉपर्टीज में आउटलेट खोलने की पेशकश की जा रही है।

हाइवे रीटेलिंग में नए अवसर

सूत्रों का कहना है कि इसका मकसद देश में बढ़ रहे हाइवे रीटेलिंग के कॉन्सेप्ट का फायदा उठाना है। एक सूत्र ने कहा, 'रीटेल डेवलपमेंट केवल उन्हीं पेट्रोल पंप्स में होगा जहां यह व्यावहारिक होगा।' इस बारे में रिलायंस रीटेल और रिलायंस बीपी ने उन्हें भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं दिया। जानकारों का कहना है कि देश में विश्वस्तरीय हाइवेज के विकास और सड़क यात्रा करने वाले लोगों की बढ़ती संख्या ने देश में हाइवे रीटेलिंग के लिए नए अवसर खोल दिए हैं।

प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक के मुताबिक 2030 तक देश में हाइवे रीटेलिंग में फूड एंड बेवरेजेज का मार्केट 2.7 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। नाइट फ्रैंक ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 2017 में देश में रोड नेटवर्क 58 लाख किलोमीटर का था जो अमेरिका के बाद सबसे बड़ा है। देश में रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर में खासकर फूड एंड बेवरेजेज में मॉडर्न रीटेल की काफी संभावनाएं हैं। रिलायंस बीपी के अभी पूरे देश में करीब 1400 पेट्रोल पंप हैं। अगले 5 साल में उसकी योजना इनकी संख्या 5,500 पहुंचाने की है।

पहले भी आजमाया था हाथ

रिलायंस ने कुछ साल पहले भी हाइवे रीटेलिंग में हाथ आजमाया था। तब उसने अपने कुछ पेट्रोल पंपों पर फूड एंड बेवरेजेज आउटलेट्स खोले थे

लेकिन तब यह कॉन्सेप्ट चल नहीं पाया था। एक सूत्र ने कहा कि अब कंपनी इसे बड़े पैमाने पर रिवाइव कर रही है। दूसरी कंपनियां भी इस बारे में पहल कर रही हैं। सिंगापुर की कंपनी क्यूब हाइवेज ने पेट्रोल पंपों पर ब्रांडेड फूड आउटलेट, कन्वीनियंस शॉप्स और टॉयलेट फैसिलिटीज विकसित करने के लिए देश की दूसरी सबसे बड़ी फ्यूल रीटेलर भारत पेट्रोलियम के साथ हाथ मिलाया है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।